यमुना पार के निवासियों का आरोप है कि प्राधिकार में भूमि एवं भवन के नाम पर विशेष सेल के गठन के बाद वास्तविक भूमि चोरों को तो बचाया जा रहा है तथा निर्दोष व्यक्तियों को आतंकित किया जा रहा है। लोगों की मांग है कि इस विशेष सेल की आड़ में की जा रही गैर-कानूनी कार्यवाही और लूट खसोट की जांच की जाय।

डी.डी.ए. की इस आतंक लीला से यमुना पार की कालोनियों में भय व आतंक व्याप्त है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध होगा कि वह तोड़ फोड़ रोक कर सभी अनधिकृत कही जाने वाली बस्तियों को नियमित करने, उजाड़े गये परिवारों को बसाने तथा लोगों को मुआवजा देने का आदेश निर्गत करें।

(iii) Need to declare Jodhpur city as B-2 city for facilities to Central Government Employees.

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि जोधपुर शहर को बी-2 श्रेणी का शहर घोषित करने हेतु अविलम्ब निर्णय लें क्योंकि यह शहर सभी मापदंड पार कर चुका है, जो किसी भी शहर को बी-2 श्रेणी प्रदान करने हेतु आवश्यक होते हैं।

13.00 hrs.

जनसंख्या की दृष्टि से भी इस शहर की जनसंख्या वर्ष 1979 के जून माह तक प्राप्त सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों के अनुसार 4 लाख 3 हजार थी, जो वर्तमान में बढ़कर करीब 4 लाख 25 हजार से ज्यादा हो गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त जनसंख्या में रक्षा प्रतिष्ठान (सैनिक, वायु सेना) में कार्यरत कर्मचारियों व उनके परिवारजनों की जनसंख्या सम्मिलित नहीं है, जो कि अलग से करीब 1 लाख 75 हजार के है।

जोधपुर शहर का औद्योगिक विकास, शहर का ऐतिहासिक महत्व, धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से बढ़ते महत्व को देखते हुए अस्थायी आने वालों की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है।

अतः वित्त मन्त्री जी से निवेदन है कि तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर जोधपुर शहर को अविलम्ब बी-2 श्रेणी का शहर घोषित कर केन्द्रीय कर्मचारियों एवं आम जनता को न्याय दें।

MR. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned for lunch and will meet at 2 P. M.

13.01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five Minutes past Fourteen of the Clock.

(SHRI HARINATHA MISRA *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377—contd.

(iv) Measures to provide uninterrupted Services by Nationalised Banks.

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : सभापति महोदय, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश की जनता ने राहत की सांस ली थी और यह महसूस किया था कि राष्ट्रीयकृत बैंक जनता की भली प्रकार सेवा कर सकेंगे। लेकिन देखने में यह आया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण निजी बैंकों के कार्यकरण से कहीं ज्यादा नीचे गिर गया है।

बैंक कर्मचारी अपने प्रबन्धकों से किसी भी विवाद के उत्पन्न हो जाने से यदा-कदा हड़ताल परचले जाने या क्लीयरिंग हाउस का कार्य न करना आदि कठिनाइयां उपस्थित कर देते हैं, जिससे इसका असर बैंक उपभोक्ताओं, व्यापारियों, उद्योग मालिकों पर पड़ता है।

बैंक कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच विवाद उत्पन्न होने से जब बैंक कर्मचारी क्लीयरिंग हाउस का काम बन्द कर देते हैं, उस समय की स्थिति काफी विकट हो जाती है।

श्री माधव राव सिन्धिया (गुना): पान के कारण सुनाई नहीं देता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली): पान उनके मुंह में है या आपके कान में? **(व्यवधान)**

श्री नवल किशोर शर्मा : श्री वाजपेयी ने मेरी मदद की है, उसके लिए धन्यवाद ।

सभापति महोदय : कान पर भी असर पड़ जाता है **(व्यवधान)**

श्री नवल किशोर शर्मा : व्यापारियों और उद्योग मालिकों का भुगतान रुका रहता है और लाखों करोड़ों रुपयों के लेन-देन बैंकों में रुके रहते हैं, या फिर व्यापारी या उद्योग मालिक बैंक का कार्य बन्द होने के कारण क्लीयरिंग से वंचित रहते हैं ।

यह भी देखा गया है कि राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मचारी अपने उपभोक्ताओं, व्यापारियों, उद्योग मालिकों को यद-कदा बे-वजह परेशान करते रहते हैं । पंजाब नेशनल बैंक, रांची और पंजाब एन्ड सिन्ध बैंक, श्रीगंगानगर (राजस्थान) के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाने से दोनों स्थानों पर स्थानीय क्लीयरिंग हाउस बन्द हैं, जिससे वहां के स्थानीय व्यापारी तथा उद्योग मालिक अपने भुगतान के न होने से परेशान हैं । श्रीगंगानगर में पिछले दो महीने से क्लीयरिंग हाउस का कार्य बन्द होने के कारण इन व्यापारियों का व्यापार ढांचा ही चरमरा गया है ।

एक और बात कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिन उपभोक्ताओं की मृत्यु हो गई है, , उनके उत्तराधिकारियों को उनके खाते में जमा-पूंजी निकालने के लिए काफी लम्बे समय तक इन्तजार करना पड़ता है और इन उत्तराधिकारियों को अनेक जटिल प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए बाध्य किया जाता है, जबकि इनको मिलने वाली राशि के बराबर तो कानूनी कार्यवाही में पूरा खर्च हो जाता है ।

मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में अविलम्ब ऐसी व्यवस्था करें कि बैंक कर्मचारियों और प्रबन्धकों के मध्य किसी भी विवाद के कारण उपभोक्ताओं, व्यापारियों, उद्योग मालिकों का भुगतान न रुका रहे और क्लीयरिंग हाउस अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके ।

(v) Recent strike by workers of clearing Agents of Bombay port.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): On account of the recent strike by the workers of the clearing Agents the operations at the Bombay port have come to a complete standstill. Many ships as a result of the strike, had to be turned away and the exporters could not execute their contracts and they were put to a heavy loss and the country also loss valuable foreign exchange. Everybody knows the position in the Bombay port and many vessels have to stay on the high seas for days together and even as long as a month, for want of berths in the port where the loading and unloading operations are going on at a snail's pace. During the strike no goods could be lifted and taken out of the port except on a permit issued by the workers' union. There is heavy congestion in the port. It is common knowledge that many exporters and importers try to avoid Bombay port and have the ships sent to Kandla or Goa. It is high time that the Government realised the gravity of the situation and took proper and firm measures to see such things do not happen in the premier port of the country.

Sir, I request the Government to take firm action.

(vi) Need to provide more facilities for the development of National School of Drama.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (New Delhi): The National School of Drama has rendered great service to the cause of Theatre in India.

During its 23 years of existence, in spite of limited resources and several other constraints the school has ad-